IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व एवं सशक्तिकरण : एक अध्ययन

डॉ. नीति मिश्रा
जनता महाविद्यालय, रीवा, म.प्र.

शोध सारांश –

पंचायत राज संस्थानों को ग्रामीण विकास की सभी समस्याओं के समाधान के रूप मे देखा जाता है और यह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन विकेंद्रीकरण प्रक्रिया और भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायती राजसंस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर एक विषयगत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें पंचायत कामकाज स्व–निर्णय लेने की क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, परिवर्तनों के बारे में प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है। उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और उनकी राजनीतिक भागीदारी में कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई के कारण काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेता कम भ्रष्ट हैं, प्रभावी मूल्य पर समान गुणवत्ता के अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और समग्र शासन में सुधार के लिए महिलाओं की प्राथमिकताओं पर विचार करती हैं।

इसके विपरीत, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि महिला प्रतिनिधि अशिक्षित है विशेषकर ग्राम विकास कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने में वे पतियों और पुरुष अधिकारियो ं पर निर्भर रहती हैं। समीक्षा से पता चलता है कि पितृसत्तात्मक और जाति– ग्रस्त समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक यात्रा आसान नहीं है, जिसके कारण ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों के प्रभुत्व के कारण महिला प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर काम करने में सहज नहीं हैं और उन्हें पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में अपनी क्षमता साबित करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा, यह पाया गया कि पुरुष प्रतिनिधि राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक समय बिताते हैं, जबकि महिलाएं घरेलू कामकाज में अधिक समय बिताती हैं। कुल मिलाकर 73वें संशोधन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई ने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्तिकरण की भावना दी है, हालांकि उन्हें अभी भी संतुलन स्तर तक पहुंचना बाकी है। जैसा कि कई शोधकर्ताओं ने माना है, अगले दशक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति, नेतृत्व भूमिका, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर और राजनीतिक जागरूकता और उपलब्धि में और प्रगति करने के लिए बाध्य हैं।

मुख्य शब्द :– पंचायती राज, महिला,सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण आदि।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-22790